भारत में समावेशी विकास : अवधारणा और चुनौतियाँ

1 सुमित कुमार 2 डॉ. जालेष्वर सिंह
1 शोध छात्र, 2 वरीय व्याख्याता
1 स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
2 अर्थशास्त्र विभाग, जे.पी. महाविद्यालय, नारायणपुर, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

सार : 'समावेशी विकास' की अवधारणा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहस और चर्चाओं में महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। सरकार ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह माना कि उच्च राष्ट्रीय आय में वृद्धि अकेले रोजगार संवर्धन, गरीबी में कमी और संतुलित क्षेत्रीय विकास या मानव विकास में सुधार की चुनौती को संबोधित नहीं करती है। समावेशी विकास का विषय हाल ही में बहुत सारे कारणों से सुर्खियों में रहा है। यह अभिविन्यास 11वीं पंचवर्षीय योजना के विषय में सबसे अधिक दिखाई देता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना आयोग की प्रस्तुति में कहा गया मूल उद्देश्य "तेज़, अधिक समावेशी और सतत् विकास" है जो स्पष्ट रूप से विकास और समावेश के बीच एक स्थायी संतुलन खोजने की आवश्यकता को दर्शाता है। बहुत से लोग 'असमानता' और 'विशिष्टता' को एक ही चीज के रूप में देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि – "एक विकास प्रक्रिया जो व्यापक–आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है"। पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित वृद्धि और विकास की दृष्टिकोण सरकार की बजटीय और राजनीतिक प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। हालांकि, समावेशी विकास और वृद्धि की दिशा में प्रयास और प्रगति काफी संतोषजनक प्रतीत होती है, फिर भी, समावेशी योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कई चुनौतियां, समस्याएं और बाधाएं सामने आई हैं, जिन्हें प्रभावी ढंग से और कुशलतापर्वक निष्पादित करने के लिए कई दृष्टिकोणों और रणनीतियों की आवश्यकता प्रतीत होती है। वर्तमान आलेख भारत में समावेशी विकास और वृद्धि को प्राप्त करने में उभरती चुनौतियों की जांच करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द : समावेशी विकास, समावेशिता, पंचवर्षीय योजना, विकास दर।

परिचय

भारतीय अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व दर से बढ़ रही है। फिर भी यह अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से बहुत दूर है। देश भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, पुराने सामाजिक अवरोधों और पारदर्शिता के अभाव के कारण जर्जर बना हुआ है। विकास सभी क्षेत्रों में समान नहीं है; और आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस विकास के दायरे से बाहर हैं। विकास की उच्च दर को बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ इस विकास को समावेशी बनाने के लिए कई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों से निपटने की आवश्यकता है। बाल श्रम का उन्मूलन, महिला सशक्तीकरण, जाति व वर्ग संबंधी अवरोधों को दूर करना और कार्य संस्कृति में सुधार कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसके लिए भारतीय समाज को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। उच्च स्थानों पर भ्रष्टाचार से निपटना, चुनावी व्यवस्था की मर्यादा को दूर करना, आंदोलन की राजनीति को तेज करना और राष्ट्रीय हितों को क्षुद्र राजनीति से ऊपर रखना देश के नीति निर्माताओं के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। समावेशी विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास, अच्छी तरह से नियोजित और लक्षित शहरी विकास, बुनियादी ढाँचा विकास, शिक्षा में सुधार, भविष्य की ऊर्जा की ज़रूरतों को सुनिश्चित करना, एक स्वस्थ सार्वजनिक–निजी भागीदारी, सुरक्षित समावेश की मंशा, विकास में समाज के सभी वर्गों को समान हितधारक बनाना और सरकार सुशासन के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत वह हासिल करे जो वह चाहता है।

दुनिया में दस सबसे अमीर लोगों में से चार या पांच भारतीय हो सकते हैं, लेकिन विडंबना अभी भी बनी हुई है कि देश में अभी भी किसान परिवार के भरण–पोषण के लिए संघर्ष कर रहा है। वे आत्महत्या के लिए विवश हो रहे हैं। इस तरह की विडंबनाओं का कारण वृद्धि और विकास में समावेश का अभाव है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि "समाज की सच्ची खुशी केवल सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को खुश करके ही महसूस की जा सकती है।" समावेशिता को देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था का मार्गदर्शन करने वाले मूल्यों का एक अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए, भारत ने सामाजिक अधिकारों के लिए एक व्यापक आधार पर उचित दृष्टिकोण अपनाया है। सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, मनरेगा आदि जैसे कई उपायों ने सामाजिक और आर्थिक समावेश को बढ़ावा देने के साथ–साथ लोगों को सशक्त बनाने पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। हालाँकि, 20 प्रतिशत से अधिक लोग अभी भी भारत में गरीबी के अधीन हैं। भारत मानव विकास सूचकांक के मामले में विश्व के कई अन्य राष्ट्रों से काफी पीछे हैं जो एक राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता को दर्शाता है। हमारे देश में जातिगत उत्पीड़न, आदिवासियों और दलितों के शोषण और सामाजिक बहिष्कार के उदाहरण असामान्य नहीं हैं। हालांकि देश ने एक लंबा सफर तय किया है, फिर भी हमें अभी बहुत आगे जाना है। इसके लिए समावेशिता एवं लोगों को शक्ति ही भविष्य है।

भारतीय अर्थव्यवस्था नई सहस्त्राब्दी में तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन यह तथ्य अभी भी बना हुआ है कि गरीब अभी भी गरीब हैं, भले ही अमीर सुपर अमीर बन गए हैं। विकास समावेशी विकास से काफी दूर है। 1990 के दशक की शुरूआत में आर्थिक उदारीकरण ने 1997 के बाद से भारत की विकास दर औसतन 7 प्रतिशत प्रति वर्ष तक बढ़ा दी है, जो 1970 के दशक में सिर्फ 3.5 प्रतिशत थी। इस अवधि के दौरान भारत ने खुद को कृषि अर्थव्यवस्था से सेवा अर्थव्यवस्था में बदल लिया है। अभी सेवा क्षेत्र का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में 55 प्रतिशत हिस्सा है। सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के वृद्धि और विकास ने अर्थव्यवस्था का चेहरा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

देश में अभी भी लोगों के एक बड़े हिस्से को दरकिनार रखकर कुछ खतरनाक रुझानों को छुपाती है, फिर भी सरकार द्वारा सभी के विकास का प्रयास जारी है। अधिकांश भारतीय गांवों में रहते हैं और वे भारत की विकास गाथा से बाहर है। ग्रामीण भारत को स्थानिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, यथा – भूमि जोत सिकुड़ रहे हैं, कृषि उत्पादन में धीमी वृद्धि और सीमित सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढाँचा है। महिलाओं, बच्चों, पिछड़ी जातियों और अन्य अल्पसंख्यकों भी करीब–करीब

विकास से वंचित हैं। भारत के लगभग दसवें हिस्से को प्रभावित करने वाले उग्रवादी आंदोलनों का उदय इस आर्थिक बहिष्कार और निचले तबके की अधूरी आकांक्षाओं का जो विकास की रोशनी से दूर है, प्रत्यक्ष परिणाम है।

भारत की बढ़ती आबादी, जिसे 2030 तक लगभग 1.5 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, को खिलाने, शिक्षित करने और रोजगार देने का काम बहुत बड़ा है। इसमें 270 मिलियन लोगों की शुद्ध वृद्धि शामिल है जो कार्यबल में जुड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के रूप में उन्हें आर्थिक मुख्यधारा में लाना किसी भी समावेशी रणनीति का आधार होना चाहिए।

आज, भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रही है। लेकिन देश में संपत्ति का वितरण अत्यधिक असमान रूप से है। क्रेडिट सुइस के अनुसार, शीर्ष 1 प्रतिशत जनसंख्या के पास भारत की 15.9 प्रतिशत संपत्ति है, शीर्ष 5 प्रतिशत के पास 38.3 प्रतिशत और शीर्ष 10 प्रतिशत के पास भारतीय धन का 52.9 प्रतिशत है। अर्थात् करीब 90 प्रतिशत भारतीयों – शहरी और ग्रामीण – गरीबों की देश की कुल संपत्ति में बहुत कम हिस्सेदारी है। अतः समावेशी विकास के लिए इस बढ़ती खाई को कम करना अत्यावश्यक है जो संपत्ति के पुनःवितरण के माध्यम से ही संभव है, जहां आबादी का अधिकांश भाग मध्यम वर्ग का है और आबादी का एक छोटा–सा प्रतिशत या तो बहुत समृद्ध है या बहुत गरीब है।

भारत इन आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ है, तो "जनसांख्यिकीय लाभांश" जो कि देश को काट सकता है, एक जनसांख्यिकीय दायित्व बन जाएगा। यह विशाल कार्य अकेले सरकार द्वारा नहीं किया जा सकता है। उद्योग और नागरिक समाज को समावेशी विकास के लिए सरकार के साथ भागीदारी करनी चाहिए। सरकार द्वारा आय असमानताओं और लोगों की बढ़ती आकांक्षाओं के प्रति जागरूक नरेगा और आधार जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से इन पर काम किया जा रहा है। सिविल सोसाइटी ने भी डिजाइन और गवर्नेंस ओवरसाइट के माध्यम से योगदान दिया है। लेकिन, इसमें अभी और द्रूत गति से काम करने की आवश्यकता है।

समावेशी विकास की अवधारणा

समावेशी विकास का मतलब मूल रूप से "व्यापक–आधारित विकास, साझा विकास और गरीब–समर्थक विकास" है। आर्थिक नीति में एक दृष्टिकोण के रूप में, यह माना जाता है कि किसी देश में गरीबी की तीव्र विकास दर में जब कमी आती है तो उस देश की विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ जाती है।

11वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि – "एक विकास प्रक्रिया जो व्यापक–आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है"। समावेशी विकास का उद्देश्य गरीबी में कमी, मानव विकास, स्वास्थ्य और काम करने और रचनात्मक होने का अवसर प्रदान करना है। संसाधनों के आवंटन को छोटे और दीर्घकालिक लाभ और बड़े पैमाने पर आर्थिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि कुछ क्षेत्रीय और जनसंख्या मानदंडों पर गणितीय रूप से समान होना चाहिए।

समावेश में चार विशेषताएं शामिल हैं – अवसर, क्षमता, पहुंच और सुरक्षा। अवसर विशेषता लोगों को अधिक से अधिक अवसर पैदा करने पर केंद्रित है और उनकी आय बढ़ाने पर केंद्रित है। क्षमता उपलब्ध अवसरों का फायदा उठाने के लिए लोगों को अपनी क्षमताओं को बनाने या बढ़ाने के लिए साधन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है। पहुंच विशेषताएँ अवसरों और क्षमताओं को एक साथ लाने के लिए साधन प्रदान करने पर केंद्रित हैं। सुरक्षा विशेषता लोगों को आजीविका के अस्थायी या स्थायी नुकसान से बचाने के लिए साधन प्रदान करती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक साथ समावेशी विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीडीपी में निरंतर विस्तार से मापा गया आर्थिक विकास सभी चार आयामों के पैमाने और दायरे के विस्तार में योगदान देता है।

भारत में समावेशी विकास की आवश्यकता

समावेशी विकास सतत् विकास और धन और समृद्धि के समान वितरण के लिए आवश्यक है। समावेशी विकास हासिल करना भारत जैसे देश में सबसे बड़ी चुनौती है। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। फिर भी, भारत अपने पड़ोसी चीन के विकास से बहुत दूर है। इसी तरह, पूरे देश के लिए 8 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि की उपलब्धि एक प्रमुख कारक है जो भारत में समावेशी विकास को महत्व देता है। इसी तरह, कम कृषि विकास, कम गुणवत्ता वाले रोजगार विकास, कम मानव विकास, ग्रामीण–शहरी विभाजन, लिंग और सामाजिक असमानता, और क्षेत्रीय असमानता आदि के मामले में बहिष्कार राष्ट्र के लिए समस्याएं हैं। समावेशी विकास के लिए गरीबी और अन्य विषमताओं को कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ाना देश का सबसे प्रमुख उद्देश्य हैं। हालाँकि भारत में बाल श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है और इस अमानवीय प्रथा को रोकने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। आज भी भारत में कई बच्चे शिक्षा से वंचित हैं क्योंकि उनको जीवन–यापन के लिए श्रम करना पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा, साक्षरता के स्तर को उच्च विकास के लिए आवश्यक कुशल कार्यबल प्रदान करने के लिए भारत में समावेशी विकास सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है क्योंकि देश में आर्थिक सुधार पुरानी दार्शनिकता तथा राजनेताओं और विपक्षी दलों के आरोप–प्रत्यारोपों से अभिभूत हैं। साथ ही, आय, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं और बाल विकास, बुनियादी ढाँचे और पर्यावरण से संबंधित निगरानी योग्य लक्ष्यों की उपलब्धि के खिलाफ समावेशी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, भारत में राजनीतिक नेतृत्व देश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन, अध्ययनों में पाया गया है कि इस देश के अधिकांश राजनेताओं में वैज्ञानिक साक्षरता का स्तर बहुत निम्न है। विभिन्न अन्य अध्ययनों ने अनुमान लगाया कि भारत में भ्रष्टाचार की लागत जीडीपी के 10 प्रतिशत से अधिक है। भ्रष्टाचार उन बीमारियों में से एक है जो समावेशी विकास को बाधित करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, असमानताओं को लेकर चिंता व्यक्त किया जा रहा है और विकास के लिए समावेशी दृष्टिकोण के बारे में भी बात कर रहे हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ग्रामीण भारत में रहने वाले एक–चौथाई लोगों को मुख्यधारा में लाना सबसे बड़ी चिंता है। विकास को समाज के सभी वर्गों और देश के सभी हिस्सों में पहुंचाने की चुनौती है। समावेशी विकास प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका विकासशील लोगों को कौशल के माध्यम से प्रशिक्षित करना है। इसलिए इस आलेख से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत को वृद्धि और विकास में समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की बहुत आवश्यकता है।

समावेशी विकास के तत्व

पूर्व प्रधानमंत्री और महान अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह ने एक बार समावेशी विकास के प्रमुख घटकों पर जोर देते हुए कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश में तेज वृद्धि, किसानों के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र में तेजी, कृषि क्षेत्र में अद्वितीय सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क के माध्यम से रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर सार्वजनिक खर्च में तेज वृद्धि अत्यावश्यक है। समावेशी विकास के विभिन्न अंतःसंबंधित तत्व निम्नानुसार गणना किए जा सकते हैं :

1. गरीबी में कमी
2. गुणवत्ता और रोजगार की मात्रा में वृद्धि।
3. कृषि क्षेत्र का विकास।
4. सामाजिक क्षेत्र का विकास।
5. अच्छी गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण प्रणाली।
6. मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) संकेतक और रैंकिंग में सुधार।
7. सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताओं के प्रभाव को कम करना।

भारत में समावेषी विकास की समस्याएँ

भारत जैसे विकासशील देश के लिए, देश की सभी प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए समावेशी विकास की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। हालांकि नई सहस्त्राब्दी में वृहद–आर्थिक स्थिरता देश के लिए सकारात्मक है। फिर भी 2008–09 में सापेक्ष विकास में कमी आई, जिसका कारण ज्यादातर वैश्विक आर्थिक गतिविधि और अस्थिर वित्तीय बाजारों के कमजोर पड़ने के प्रभाव से हुआ। समावेशी विकास हासिल करने के लिए भारत जैसे विकासशील देशों के लिए निम्नलिखित समस्याएं प्रमुख चिंताएं हैं जो निम्न हैं – (1) गरीबी, (2) रोजगार, (3) कृषि, (4) सामाजिक विकास में समस्याएं और (5) क्षेत्रीय विषमताएं।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए सकारात्मक कार्रवाई के साथ, समावेश की दृष्टि को अवसर की समानता के साथ–साथ आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता के लिए गरीबी उन्मूलन के पारंपरिक उद्देश्य से परे, स्वतंत्रता और सम्मान के साथ सभी के लिए अवसर की समानता – सामाजिक या राजनीतिक बाधाओं के बिना यह आर्थिक और सामाजिक उन्नति के अवसरों में सुधार के साथ होना चाहिए। विशेष रूप से, वंचित समूहों से संबंधित व्यक्तियों को अपने कौशल को विकसित करने और विकास प्रक्रिया में भाग लेने के लिए विशेष अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

यह परिणाम तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब सशक्तिकरण की डिग्री हो जो एक लोकतांत्रिक राजव्यवस्था में आवश्यक भागीदारी की सच्ची भावना पैदा करे। क्योंकि वंचित और हितग्राहित हाशिए पर रहने वाले समूहों का सशक्तिकरण समावेशी विकास के किसी भी दृष्टिकोण का एक अनिवार्य हिस्सा है। भारत की लोकतांत्रिक राजनीति, पंचायती राज संस्थान स्तर पर लोकतंत्र की त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की स्थापना के साथ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण के साथ सभी समूहों के सशक्तिकरण और भागीदारी के अवसर प्रदान करती है। स्थानीय स्तर पर शक्ति और जिम्मेदारी के अधिक प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से इन संस्थानों को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

भारत में समावेषी विकास की चुनौतियाँ

समावेशी विकास रणनीति के प्रमुख घटकों में ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश में तेज वृद्धि, ग्रामीण बुनियादी ढाँचा और किसानों के लिए कृषि का श्रेय; एक अद्वितीय सामाजिक सुरक्षा नेट के माध्यम से ग्रामीण रोजगार में वृद्धि और शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर सार्वजनिक खर्च में तेज वृद्धि है। सरकार को वंचितों को सशक्त बनाने के लिए कई तरह के विधायी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। भारत में समावेशी विकास रणनीतियों के समक्ष कुछ चुनौतियाँ और अवसर हैं –

1. गरीबी उन्मूलन
2. कृषि विकास
3. अच्छी और ईमानदार सरकार और सरकार की योजनाएं।
4. बाल श्रमिक एक जटिल समस्या है जो मूल रूप से गरीबी में निहित है।
5. भारतीय .. सामाजिक विकास
6. महिला सशक्तिकरण
7. क्षेत्रीय विषमताओं का उन्मूलन।
8. रोजगारोन्मुख शिक्षा

भारत सरकार ने नवीन, लचीली और सुधार उन्मुख सुविधाओं के साथ कई पहल शुरू करके समावेशी विकास के लिए कदम बढ़ाया है –

1. ग्रामीण आधारभूत संरचना (भारत निर्माण)
2. रोजगार (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना)
3. क्षेत्रीय विकास (पिछड़ा जिला विकास कार्यक्रम)
4. शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)
5. ग्रामीण स्वास्थ्य (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन)
6. शहरी आधारभूत संरचना (राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन)

अधिक समावेशी विकास के लिए रणनीति

आर्थिक विकास और गरीबी में कमी के बीच संबंधों के बारे में अनुभवजन्य साक्ष्य बताते हैं कि कोई भी विशेष विकास मॉडल विशिष्ट रूप से गरीब–समर्थक नहीं है और इस मामले को केवल मामला–दर–मामला स्तर पर अनुभवजन्य रूप से माना जा सकता है। फिर भी, गरीब–समर्थक विकास के प्रमुख स्रोतों के बारे में कुछ सामान्य निष्कर्ष निकालना संभव है। अंतरराष्ट्रीय साक्ष्य बताते हैं कि गरीबी में कमी के प्रयासों से कृषि में तेजी से वृद्धि, सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और शासन की गुणवत्ता में मदद मिली है।

कृषि में वृद्धि : रावलियन और दत्त (1996) ने पाया कि अधिकांश विकासशील देशों में गरीबी ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित है। कृषि क्षेत्र में विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए अत्यधिक लाभकारी है। चीन के एक अन्य अध्ययन में, रावलियन और चेन (1997) ने पाया कि प्राथमिक क्षेत्र में हेडकाउंट गरीबी में कमी का प्रभाव माध्यमिक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र के प्रभाव से 3.5 गुना अधिक है।

हरित क्रांति के मद्देनजर भारत का कृषि क्षेत्र मजबूती से विकसित हुआ। लेकिन, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान हाल के दशकों में गिरावट पर रहा है। 1980 में सकल घरेलू उत्पाद का 36 प्रतिशत से गिरकर 2007 में लगभग 18 प्रतिशत हो गया है। कृषि में मंदी ने देश के कई हिस्सों में ग्रामीणों के सम्मुख संकट उत्पन्न किया है और छोटे एवं बड़े दोनों किसानों को प्रभावित किया है जिससे वे पलायन को मजबूर हुए हैं, जिसका दुष्प्रभाव शहरी क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि की वृद्धि दर के लगभग दोगुने होने को शामिल करते हुए त्वरित विकास की रणनीति विकसित की है।

बुनियादी ढांचे और ऊर्जा : भारत की आर्थिक विकास रणनीतियों में बुनियादी ढांचा केंद्रीय स्तर पर कायम है। ऊर्जा की कमी की समस्या भारत के सामने आने वाली कई अवसंरचना चुनौतियों में से एक है, क्योंकि बुनियादी ढांचे के अधिकांश अन्य रूपों में आर्थिक विकास की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त विस्तार और उन्नयन की आवश्यकता है। भारतीय बुनियादी ढांचे पर दबाव विभिन्न स्रोतों से आता है, जिसमें व्यापार का तेजी से विस्तार, विनिर्माण की उच्च वृद्धि के लिए एक नई प्राथमिकता, शहरीकरण की तीव्र गति, कृषि के पुनरूद्धार और विविधीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थितियों में सुधार की आवश्यकता शामिल है। ये दबाव देश भर में लोगों और सामानों में गंभीर अड़चनों के रूप में प्रकट होते हैं, और अधिकांश आबादी के लिए बिजली, पीने के पानी और स्वच्छता के लिए उप मानक उपयोग में होते हैं। भारत की बुनियादी सुविधाओं की तुलना कई अन्य एशियाई देशों के साथ प्रतिकूल रूप से होती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2016 तक जीडीपी के 7–8 प्रतिशत तक बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने का प्रस्ताव है।

शिक्षा पर सार्वजनिक परिणाम : कई अध्ययनों से पता चलता है कि समावेशी आर्थिक विकास और सामाजिक विकास पर सार्वजनिक व्यय के स्तर के बीच सकारात्मक संबंध है। साक्षरता, कोई संदेह नहीं है, गरीबी में कमी का सबसे महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि यह रोजगार में वृद्धि करता है। 2009 में, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी देते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। 86वें संशोधन अधिनियम ने शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। 2003–2009 के बीच प्राथमिक शिक्षा में नामांकन की संख्या 57 मिलियन से बढ़कर 192 मिलियन हो गई है। अनुमानित आठ मिलियन बच्चे, जो स्कूलों में नहीं आते हैं, कार्यक्रम से लाभान्वित होने की उम्मीद है। (विश्व बैंक, 2010)

भारत में साक्षरता (5 वर्ष और उससे अधिक) 1951 में 18.3 प्रतिशत से बढ़कर 1981 में 43.6 प्रतिशत, 2005 में 65.2 प्रतिशत और 2011 में यह 74 प्रतिशत हो गई। हालांकि, साक्षरता का स्तर राज्यों, लिंग और ग्रामीण–शहरी क्षेत्रों में काफी भिन्न है। विभिन्न आयु समूहों में शहरी–ग्रामीण साक्षरता दर में बड़े अंतर हैं।

स्वास्थ्य सेवा पर सार्वजनिक परिणाम : स्वास्थ्य देखभाल पर भारत का सार्वजनिक व्यय, सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 प्रतिशत पर, देश के मानकों को विकसित करने से भी कम रहा है। जबकि भारत के पड़ोसी देशों – पाकिस्तान (1.0), बांग्लादेश (1.5), नेपाल (1.5), श्रीलंका (1.8) और भूटान (3.6) अधिक है। स्वास्थ्य सेवा पर भारतीय व्यय को भी सकल घरेलू उत्पाद के 1.05 प्रतिशत से 0.9 प्रतिशत तक घटा दिया गया है। इस प्रकार जीडीपी में वृद्धि स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च में वृद्धि में तब्दील नहीं हुई। तुलनात्मक रूप से, अधिकांश देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय उनके सकल घरेलू उत्पाद का लगभग पांच प्रतिशत है जबकि भारत न केवल समग्र स्वास्थ्य पर कम खर्च करता है, बल्कि सार्वजनिक व्यय भारतीय समाज के समृद्ध तबकों का पक्षधर है।

आर्थिक विकास के इस चरण में भारत को अपनी संपूर्ण आबादी के लिए दवाओं सहित स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक नए मॉडल पर विचार करने की आवश्यकता है। भारत की तीन प्रतिशत से कम आबादी के पास निजी स्वास्थ्य बीमा है। स्वास्थ्य सेवा में दीर्घकालिक योजना के लिए एक महत्वपूर्ण कारक यह है कि भारतीय अब एक सदी पहले की तुलना में काफी लंबे समय तक जी रह रहे हैं और औसत आबादी का औसत आयु धीरे–धीरे बढ़ना शुरू हो गया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना और समावेशी विकास

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने आर्थिक बुनियादी ढांचे में कई आयामों में गुणात्मक सुधार हुआ है जबकि 2011–12 में विकास दर की गति धीमी रही। 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर औसतन 8 प्रतिशत रही जो लक्ष्य 9 प्रतिशत से कम थी फिर भी यह 10वीं पंचवर्षीय योजना के विकास दर 7.8 प्रतिशत से अधिक रहा। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सरकारी खर्च के माध्यम से भारत के कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के विकास को प्रोत्साहित करना प्राथमिकता में रही। यह भारत के विनिर्माण क्षेत्र के विकास के माध्यम से रोजगार पैदा करने और देश को मूल्य श्रृंखला से ऊपर ले जाने की ओर अग्रसर हुआ। "समावेशी विकास" उत्पन्न करने का एक महत्वपूर्ण पहलू ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सहायता के लक्ष्य को स्थानांतरित करना है।

योजना आयोग की प्रस्तुति में कहा गया मूल उद्देश्य "तेज़, अधिक समावेशी और सतत् विकास है।" यह कहा गया था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में किसानों, लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों आदि की बेहतरी होगी। योजना आयोग द्वारा यह दावा किया जाता है कि विकास के लिए हमें और अधिक समावेशी होने की आवश्यकता है: –

- कृषि में बेहतर प्रदर्शन।
- तेजी से नौकरियों का सृजन, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और कौशल विकास पर मजबूत प्रयास।
- गरीबों के लिए प्रत्यक्ष कार्यक्रमों की बेहतर प्रभावशीलता।
- सामाजिक रूप से कमजोर समूहों के लिए विशेष कार्यक्रम।
- वंचित या पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम।
- वित्तीय संस्थागत ऋण की पहुंच।

- कुशल और स्वस्थ कार्यबल।
- नवाचार को कम करना
- छोटी कंपनियों की विकास क्षमता को बढ़ावा देना,

समावेशी विकास के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा। भारत के पास एक अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है और उस विकास को समावेशी बनाने का अनूठा अवसर है, बशर्ते कि समाज के सभी वर्गों की ओर से गंभीर, सतत् और उद्देश्यपूर्ण योजना के साथ कठिन और अनुशासित काम करने की इच्छा हो। 12वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास और सतत् विकास की समस्या को दूर करने के लिए तीन वैकल्पिक परिदृश्यों का सुझाव दिया है : पहला, 'मजबूत समावेशी विकास', दूसरा 'अपर्याप्त कार्रवाई' और तीसरा 'पॉलिसी लॉगजम'।

भारत की क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया जाना चाहिए। बेहतर प्रशासन, अधिक और बेहतर शिक्षण संस्थान, उच्च कृषि उत्पादकता, नियंत्रित मुद्रास्फीति और बुनियादी ढांचे में सुधार इस दिशा में आवश्यक कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण कदम हैं।

बेहतर प्रशासन समय की आवश्यकता है, लगभग सभी आवश्यक क्षेत्रों में यथा स्वास्थ्य, स्वच्छता और पानी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में। यह ऐसे सामाजिक क्षेत्र है जिस ओर राजनीतिक दल कम से कम दिलचस्पी लेते हैं, खासकर चुनावोपरान्त सत्ता में आने के बाद। फिर भी ये ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह समझने की आवश्यकता है कि सरकार की नीतियां और व्यवहार सभी प्रकार की घरेलू और पूर्वाभास, औपचारिक और अनौपचारिक, छोटे और बड़े, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अवसरों और प्रोत्साहनों को कैसे आकार देते हैं। एजेंडा व्यापक और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस पर पहुंचाना गरीबी को कम करने, जीवन स्तर में सुधार और अधिक समावेशी, संतुलित और स्थिर दुनिया बनाने की कुंजी है।

समावेशी विकास के लिए सुझाव

1. आर्थिक विकास के लिए इक्विटी महत्वपूर्ण है इसलिए इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2. आर्थिक विकास के लिए कृषि विकास आवश्यक है।
3. आर्थिक सुधार महत्वपूर्ण हैं। लेकिन वृहद–गरीब नीतियों (राजकोषीय, व्यापार, वित्तीय, मौद्रिक आदि) पर गरीबों का ध्यान केंद्रित होना चाहिए।
4. संरचनात्मक परिवर्तन के बाद कृषि–उद्योग–सेवाओं के अनुक्रम का पालन किया जाना चाहिए।
5. उत्पादक रोजगार के निर्माण के लिए विनिर्माण क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण है।
6. अवसरों की समानता (शिक्षा) दी जानी चाहिए।
7. वितरण प्रणाली में सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना
8. संसाधनों का विकेंद्रीकरण करना चाहिए।
9. महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का महत्व
10. सामाजिक–राजनीतिक वातावरण के संबंध में आर्थिक सुधार
11. उच्च विकास के लिए आवश्यक कुशल कार्यबल प्रदान करने के लिए साक्षरता का स्तर बढ़ाना होगा।
12. आर्थिक वितरण में महत्वपूर्ण सुधार लाने होंगे।

निष्कर्ष

भारत प्राचीन काल से ही दुनिया के कुछ सबसे जरूरी खनिजों, खूबसूरत जगहों, विविध संस्कृतियों और सक्षम और प्रतिभाशाली लोगों से समृद्ध रहा है। यह वह समय है जब हम भटकना बंद कर देते हैं और लाभ उठाते हैं और उन सभी चीजों का लाभ उठाते हैं जिनके बारे में ज्यादातर देश कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। इसके लिए बहुत कुछ किया जाना है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए, तो हमें दुनिया के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। इस प्रकार अब समय समावेशी भारत की ओर त्वरित कदम उठाने का है और हम सभी को समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में हाथ मिलाना चाहिए और हमारे सेवा क्षेत्र को विकसित करने से हमें इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी जो कि समय की आवश्यकता है इसलिए हमें इस पर काम करना चाहिए। समावेशी विकास रणनीतियों के स्रोतों को मजबूत करने के लिए कई उपायों की रूपरेखा निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर है –

- कृषि में रोजगार और विकास।
- शिक्षा और स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि।
- सभी क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचे
- सभी स्तरों पर अधिक प्रभावी शासन।

संदर्भ

अनंत, एस. और ओंवुफ, एस. (2013). ''भारत में विनीय समावेशन की चुनौतियां : आंम्र प्रदेश का संदर्भ'', *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, अंक 48, सं. 7, 16, फरवरी, 2013, पृ. 77–83.

केंद्रीय बजट, 2011–12 / 2015–16.

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली–110001.

बारहवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली–110001.

यूएनडीपी रिपोर्ट–2010

योजना (अगस्त 2015). प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

योजना आयोग (2011). तेज, सतत् और ज्यादा समग्र विकासः बारहवीं पंचवर्षीय योजना का नजरिया, भारत सरकार, दिल्ली।

योजना आयोग (2013). गरीबी के अनुमान पर बेस नोट, 2011–12 भारत सरकार।

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य रिपोर्ट–2014, संयुक्त राष्ट्रं द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, 2014.

Bahuguna, Sunderlal. Sustainable Development in India. Perspective. www.moel nid/wse*d/doc*/consul_book_persp pdf.

Datt, Gaurav & Ravallion, Martin. (2010). Shining for the poor too? *Economic and Political Weekly*, 45(7), 55-60.

Dev, Mahendra S. & Ravi, C. (2007). Poverty and inequality: All India and states, 1983-2005. *Economic and Political Weekly*, 42(6), 509-521.

Himanshu, H. (2007). Recent trends in poverty and inequality: Some preliminary results. *Economic and Political Weekly*, 42(6), 497-508.

Ravallion, Martin and Chen, Shaohua (1997). What Can New Survey Data Tell Us about Recent Changes in Distribution and Poverty?, *The World Bank Economic Review*, 11(2): 357-82.

Ravallion, Martin; Datt, Gaurav (*January* 1996). How important to India's poor is the sectoral composition of economic growth? (English). *The World Bank economic review*, 10(1):1-25.

http://www.planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/11th/11_v1/11v1_ch1.pdf

http://www.planningcommission.nic.in/reports/genrep/Inter_Exp.pdf

http://planningcommission.gov.in/plans/planrel/12thplan/welcome.html

http://www.worldbank.org